

विचार

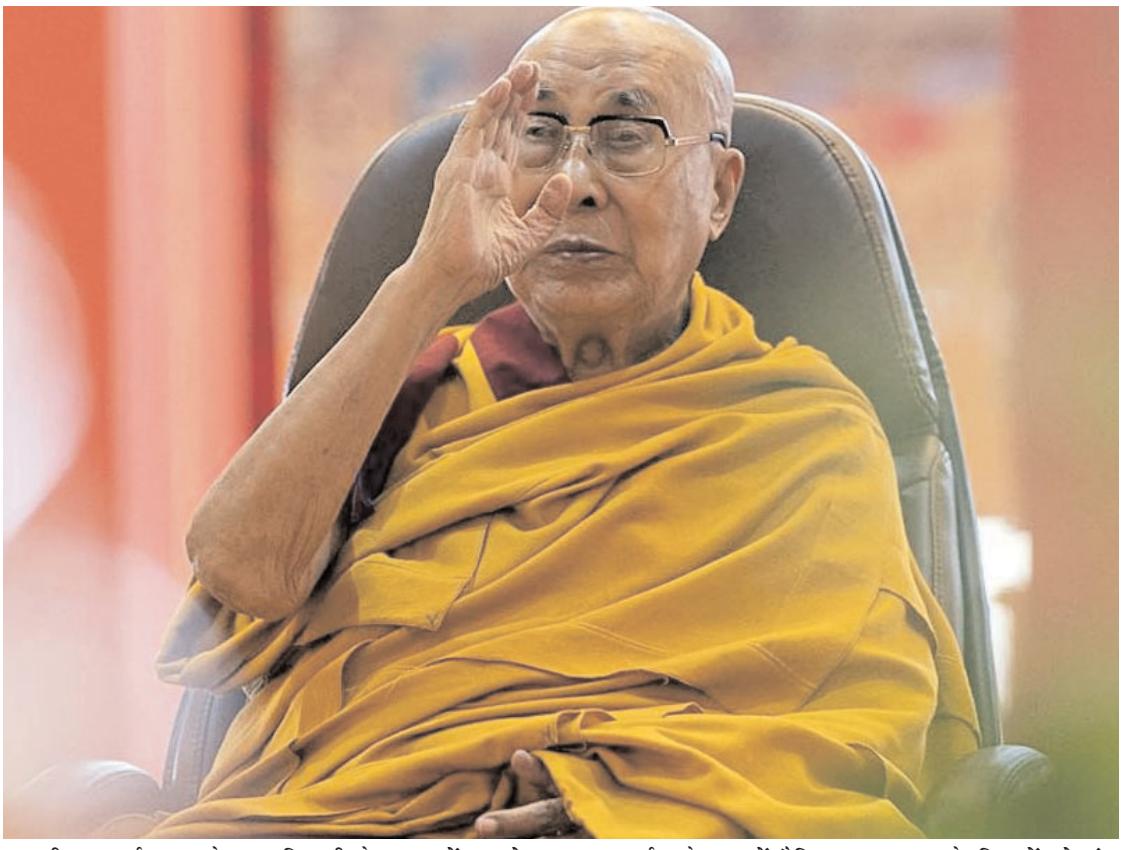
कर्नाटक में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गलती दोहरा रही है

कर्नाटक में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। यह जीत केवल भाजपा को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया था कि यदि पार्टी एकजूट और ठोस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे तो वह भाजपा को धेर सकती है। लेकिन अब, कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और लगातार सांवर्जनिक रूप से सामने आने वाले मतभेदों ने सबाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस यहां पर वही गलती दोहरा रही है जो उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की थी? हम आपको याद दिला दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के विवाद कांग्रेस के लिए दीर्घांकिक सिरदर्द बना रहा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता-सांझादारी को लेकर विवाद लगातार सामने आता रहा था। ऐसा ही वाक्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच देखने को मिला था। ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गये थे जिससे कमलनाथ की सरकार बीच में ही गिर गयी थी। तीनों ही राज्यों में मतभेद पार्टी मंच के बजाय मीडिया में उछलते रहे, जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल गया। इसी तरह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है कि आलाकमान द्वारा समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाने के कारण टकराव बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद से ही यह स्पष्ट था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। समझौते के तहत सिद्धारमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवकुमार खेमा इसे अंदर ही अंदर चुनौती दे रहा है। कर्नाटक में मत्रिमंत्री विस्तार की बात हो चाहे प्रशासनिक निर्णयों की बात हो या पिर रणनीतिक घोषणाओं की बात हो, सभी मामलों में दोनों नेताओं के बीच मतभेद लगातार उत्तराग्रह होते रहते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी खुलेआम एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं। डीके शिवकुमार के समर्थक अक्सर उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित करते हैं जो सिद्धारमैया समर्थकों को असहज करता है और इसके चलते दोनों और से बयानबाजी शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि देश में सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और देखने में आ रहा है कि तीनों जगह पार्टी में कलह है। कर्नाटक के साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन कर्नाटक की कलह कुछ ज्यादा ही उत्तराग्रह हो रही है। यही नहीं, कर्नाटक के विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे द्वारा हाईकमान पर टालना दर्शाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और सब कुछ ऊपर से ही मैनेज हो रहा है, तभी इस प्रकार का टकराव बना हुआ है। देखा जाये तो कांग्रेस इस समय देश में मुख्य विपक्षी पार्टी है इसलिए सबाल उठता है कि जब वह अपना घर ही नहीं संभाल पायी हो तो देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे नियमायेगी? कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को भी एकजूट रख पाने में विफल रही है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि केरल और हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सरकार में आना तय माना जा रहा था लेकिन अपने ही नेताओं के आपसी झगड़ों की बदौलत पार्टी सत्ता से बहुत दूर रह गयी थी। इससे सांबित होता है कि कांग्रेस को हमेशा अपनों ने ही लटाई है लेकिन फिर भी पार्टी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। उधर, कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों धुरंधर नेताओं के समीकरणों पर और करें तो आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़े कुरबां समूदाय से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बड़े जनाधार बाले नेता हैं। वह सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और उन्हें पता है कि चुनावों में भाजपा के जितागत समीकरणों को कैसे बिगाड़ा है। वर्ती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आधिकारी-सामाजिक रूप से संपन्न वोकलिंग समूदाय से आते हैं। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

दलाई लामा के घर पर चीन का साजिशपूर्ण हस्तक्षेप

तिब्बत के आध्यात्मिक नेता एवं वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ज्यात्सो की जारी विवाद विवरण और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी

तिब्बत की संस्कृति से जुड़ा विषय है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चीन द्वारा इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह वैश्विक जनमत की भी अवहेलना है। इन स्थितियों में जारी विवाद विवरण और भारत के मसले पर भारत की भूमिका एक निर्णायक मार्गदर्शक के रूप में उभरती है और इसे दृष्टि में रखते हुए भारत ने दलाई लामा का पक्ष लिया है। ऐसा करने में कृष्ण भी अप्रत्याशित नहीं हैं। भारत शुरू से तिब्बतियों के अधिकार, उनके हितों और उनकी परंपराओं व मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहा है। इन स्थितियों में जारी विवाद विवरण और भारत के मसले पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी।



चीन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि यह धार्मिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का हस्ता है। हालांकि, दलाई लामा और तिब्बती समूदाय का कहना है कि यह अधिकार के बावजूद विवाद की अधिकारी नहीं है। उनका इशारा चीन की स्वतंत्रता के उल्लंघन है। चीन, 'स्वर्ण कलश' प्रणाली का उपयोग करके अपने पर्सेन्ट्री उम्मीदवारों को स्थापित करना चाहता है। चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उसे 'स्वर्ण कलश' प्रणाली के माध्यम से है, जो 1793 में किंग राजवंश के समय से चली आ रही है। इस प्रणाली में, सभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक कलश में डाले जाते हैं और फिर एक नाम निकाला जाता है।

दलाई लामा के विवाद के धार्मिक नेता नहीं हैं, वे तिब्बती अस्तिता, स्वतंत्रता और अत्म-सम्मान के प्रतीक हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ज्यात्सो, 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण असमर्थन के बावजूद रह रहा है। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

1959 में जब दलाई लामा को कम्युनिस्ट सरकार के दमन

के चलते भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं— चीन बेहद ताकतवर हो चुका है और तिब्बत कमज़ोर। इसके बाद भी अगर तिब्बत का मसला जिंदा है, तो वजह है दलाई लामा। चीन इसे समझता है और इसी वजह से इस पद पर अपने प्रधान वाले किसी शब्द को बैठना चाहता है। चीन की योजना है कि जब वर्तमान दलाई लामा का देहांत हो, तो वह अपनी पसंद का एक 'दलाई लामा' घोषित करें, जिसे वैश्विक समूदाय भले ही स्थीकार करे, लेकिन चीन उसकी वहचान का जबरन वैधता प्रदान करे। यह एक राजनीतिक कठपुतली खड़ी करने जैसा है, जिसके उपरांत विवाद विवरण के बावजूद भी भारत और अपनी रणनीतिक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

चीन ने तिब्बत की पहचान को मिटाने की हर सुप्रकार कोशिश कर रही है। दलाई लामा के पद पर दावा ऐसी ही एक और कोशिश है। उसकी वजह से यह मामला धर्म से आगे बढ़कर वैश्विक राजनीति का रूप ले चुका है, जिसका असर भारत और दूसरे देशों पर पड़े हैं, जहां तिब्बत के लोगों ने शरण ली है। भारत पर तो चीन लंबे समय से दबाव लगाता रहा है कि वह दलाई लामा को उसे सौंप दे। चीन और तिब्बत की लड़ाई भारतीय धर्म पर दशकों से चल रही है और नई दिल्ली-पैदिंग के बीच तानव का एक बड़ा कारण बनती रही है। दलाई लामा की घोषणा के अनुसार, उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बावजूद की हो सकता है— अनुचित हस्तक्षेप के बावजूद भी यह दलाई लामा को उत्तराधिकारी तिब्बत के बावजूद उत्तराधिकारी तिब्बत के अनुसार हो सकता है। भारत को इस पर एक सौंप देने की ओर बदल रहा है। लेकिन इसमें भारत के लिए एक बड़ा समर्थन, कम्पूटरिंग दबाव और अंतरराष्ट्रीय समर्थन यैतायर करना चाहिए। अब जबकि दलाई लामा सूखा रहा है, तो यह नानव और बदलता है। लेकिन इसमें भारत के लिए एक बड़ा समर्थन, कम्पूटरिंग दबाव और अंतरराष्ट्रीय समर्थन यैतायर करना चाहिए। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ समन्वय स्थापित करें। इस परिवर्तन के बावजूद भी यह दलाई लामा का उत्तराधिकारी तिब्बत के अनुसार हो सकता है। भारत में जिसका उत्तराधिकारी तिब्बत के अनुसार हो सकता है, तो यह दलाई लामा का उत्तराधिकारी तिब्बत के अनुसार हो सकता है। अमेरिका में तिब्बती बौद्धों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोन

विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर¹
एसडीएम द्वारा किया गया आकस्मिक निरीक्षण

मांडिया आडोर, एम्सबी
(निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) लिंगराज सिद्धार द्वारा
आज शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक
एवं हाई स्कूल चनवारीडाँड़ का
आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय
परिसर, सभी कक्षाओं एवं शोचालयों
की साफ-सफाई एवं सुव्यवस्था का
सूक्ष्म अवलोकन किया तथा
विद्यालय में बनी स्वच्छता व्यवस्था
की सराहना की। अनुविभागीय
अधिकारी ने छात्रों से सीधे संवाद
कर उनकी पढाई, उपस्थिति,
सुविधाएं और आवश्यकताओं के
संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा
उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित
किया। उन्होंने कक्षाओं की दीवारों
पर अकित प्रेरणादायक उद्घरणों की
विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए इसे
विद्यार्थियों के लिए प्रेरक बताया।
निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय
अधिकारी ने पीएम श्री स्कूल मिडिल



जिले में 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में वर्ष 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में वाहनधारकों की सुविधा हेतु 5 जुलाई 2025 को मनेंग्राम के झगराखांड स्थित कशफ परिवहन सुविधा केन्द्र में एकदिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया के अनुसार यह शिविर उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके वाहनों में अब तक एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाई गई है। शासन के निर्देशनानुसार सभी पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना आवश्यक है ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को और बेहतर किया जा सके। शिविर में वाहनधारक अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

यह प्लेट वाहन की पहचान को सुरक्षित बनाती है और चोरी या फर्जी नंबर प्लेट के मामलों में नियन्त्रण हेतु अहम भूमिका निभाती है। जिला परिवहन विभाग ने सभी संबंधित वाहनधारकों से अपील की है कि वे समय पर शिविर में पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करें क्योंकि नियत समय के पश्चात एचएसआरपी नहीं लगाने पर नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

A group of six men are standing outside a building with a metal grating window. The man in the center foreground, wearing a blue shirt and white pants, is holding a white cloth-wrapped item. The other men are dressed in various casual attire, including a turbaned man on the left and a man in a white shirt on the right holding a bag.

सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की प्रक्रिया को सरल एवं समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन पैकरा एवं सहायक बीईओ वीरेन्द्र पाण्डेय भी निरीक्षण में उपस्थित रहे।

**किसानों को निःशुल्क मूँगफली बीज एवं
अरहर मिनीकीट का किया गया वितरण**



जिले में 43 वाहन चालकों के ड्रायविंग लाइसेंस निलंबित

**तीन माह तक वाहन
चलाने पर लगा रोक**

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी
(निप्र)। जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए जिला परिवहन विभाग ने सुरीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के तहत 43 वाहन चालकों के ड्रायविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं यात्रावात नियमों के उल्लंघन के

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी
(निप्र)। जिले के दूरस्थ ग्रामीण
अंचलों में तिलहन फसलों के क्षेत्र
विस्तार और उत्तादन बृद्धि को
लेकर कृषि विभाग द्वारा एक
महत्वपूर्ण पहल की गई है। नेशनल
मिशन ऑन इडिल ऑयल योजना
के अंतर्गत किसानों को उन्नत
किस्म के मूँगफली बीज और
अरहर मिनीकीट का निशुल्क
वितरण किया जा रहा है, जिससे
उन्हें वैकल्पिक फसलों के प्रति
प्रोत्साहित किया जा सके। इसी क्रम
में 01 जुलाई 2025 को
विकासखंड भरतपुर की ग्राम
पंचायत बहरासी एवं खर्मोरौद्ध में
बीज वितरण कार्यक्रम का
आयोजन किया गया। कार्यक्रम में
जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति
की अध्यक्ष श्रीमती सुखमंती सिंह,
जनपद अध्यक्ष माया प्रताप सिंह,
स्थानीय जनपद सदस्यगण एवं
सरपंच महोदयाओं की गरिमामयी

किसानों को न केवल बीज वितरित किए गए, बल्कि तिलहन एवं दलहन फसलों के महत्व और लाभों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को धान के साथ-साथ दलहन एवं तिलहन की खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों को तिलहन फसलें न केवल भूमि की उर्वरातों को बनाए रखती हैं, बल्कि कम लागत में अधिक लाभ की संभावना भी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही अरहर जैसी दलहन फसलें भी मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती हैं और पोषण रसक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इस बीज वितरण कार्यक्रम के माध्यम से दलहन फसलों के प्रति रुचि बढ़ी है और आने वाले समय में जिले में इन फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय में ये परिवर्तित करने की दिशा में यह पहल एक मजबूत

जिला पंचायत सीर्डओ ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण

सीईओ ने बरदर, शिवपुर और पोड़ीडीह पंचायतों की प्रधानमंत्री आवास, अमृत सरोकर, जल संरचना सहित अन्य विकास कार्यों की ली जानकारी

मीडिया ऑडीटर, एम्सीबी
(निप्र)। कलेक्टर डॉ. राहुल वैकेट
के निर्देशानुसार आज जिला पंचायत
सोइओ श्रीमती अंकिता सोम द्वारा
जनपद पंचायत खड़गांव अंतर्गत
ग्राम पंचायत बरदर और शिवपुर में
प्रधानमंत्री आवास योजना के
अप्रारंभ एवं प्रगतिरत आवासों का
निरीक्षण किया गया। उन्होंने
निर्माणाधीन घरों के हितग्राहियों से
चर्चा करते हुए उन्हें जल्द-से-जल्द
निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण कराने
की समझाइया दी।

A group of nine people are gathered on a concrete embankment. On the left, a man in a yellow t-shirt and grey pants stands looking towards the right. Next to him is a man in a light pink shirt and black pants. In the center, a woman in an orange dress is facing away from the camera. To her right, a man in a light blue polo shirt and beige pants is looking down at the ground. Further right, a man in a white polo shirt and grey pants stands near a hole in the embankment. On the far right, a man in a white shirt and dark trousers is sitting on the edge of the embankment, looking towards the water. The background shows a dry, rocky shoreline with some sparse vegetation and hills under a cloudy sky.

A woman with long dark hair tied back, wearing an orange sari with a subtle pattern, stands outdoors. She is looking towards the left. To her left, a large, light-colored pillar or post stands vertically. In the background, there is a building with a tiled roof and some trees under a clear sky.

जिला प्रशासन का
सख्त निर्देश सभी
अधिकारी-कर्मचारी
पहनें हेलमेट वरना
झोपड़ी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्टर की सुरक्षा में सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस दिशा में ठोस एवं कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला मुख्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यस्थल पर आने-जाने के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी हेलमेट नहीं पहनते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। चार पहिया वाहनों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित की गई है।

हांग उंहांग पह ना नानादारत
किया कि सभी विभाग प्रमुख
अपने अधीनस्थों को इस संबंध में
स्पष्ट निर्देश जारी करें। सड़क
सुरक्षा को लेकर एक प्रभावी
रणनीति तैयार करने पर जोर देते
हुए कलेक्टर ने कहा कि जिला
प्रशासन इस दिशा में कठोरता और
सतर्कता दोनों के साथ कार्य
करेगा। उन्होंने विभिन्न विभागों
को आपसी समन्वय स्थापित कर
कार्य योजना निर्धारित करने के
भी निर्देश दिए ताकि जिले में
सड़क दूर्घटनाओं में कमी लाई जा
सके और एक सुरक्षित यातायात
व्यवस्था विकसित की जा सके।
बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा
कि सड़क सुरक्षा केवल एक
अधियान नहीं, बल्कि यह प्रत्येक
नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है
और इसमें किसी भी स्तर पर
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की



हर कर्ग को सम्मान और बराबर के अवसर मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय के पथ पर अग्रसर



सामाजिक समरसता कार्यक्रम

सायं 6:00 बजे | दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

अपराह्न 4:00 बजे | आई एस बी टी, ग्वालियर

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

गरिमामयी उपस्थिति

ज्योतिरादित्य सिंधिया

केन्द्रीय मंत्री, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

नरेन्द्र सिंह तोमर

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा

5 जुलाई, 2025

समरस समाज की स्थापना के सतत प्रयास

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि मह, महानिर्वाण स्थल दिल्ली, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा स्थल लंदन 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' में सम्मिलित

मह को अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित करते हुए अम्बेडकर इंटरनेशनल एसर्च सेंटर एवं स्मारक संग्रहालय का विकास एवं मह देलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ अम्बेडकर नगर स्टेशन

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना - स्व-रोजगार के लिए डेयरी इकाई लगाने हेतु ₹42 लाख तक क्रण
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना - अनुसूचित जाति के युवाओं को ₹1 लाख तक की स्व-रोजगार अनुदान सहायता
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना - एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता
- अम्बेडकर गौ-शाला विकास योजना - आधुनिक गौ-शालाओं हेतु 125-150 एकड़ शासकीय भूमि आवंटन

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुस्तकालय योजना - अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को 10वीं-12वीं में सर्वोच्च अंक लाने पर ₹30 हजार का पुस्तकालय
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना - अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हेतु अम्बेडकर फैलोशिप
- भोपाल में मध्यप्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम डॉ. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य - सागर में 258.64 कर्ग कि.मी. में प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य

